**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2059**

**सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**सौर ऊर्जा के उत्‍पादन में निवेश**

**2059. श्री प्‍यारीमोहन महापात्र : क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. सौर ऊर्जा के उत्‍पादन में सरकारी तथा निजी कम्‍पनियों द्वारा कितना-कितना निवेश किया गया है;
2. इस संबंध में अपर्याप्‍त लक्ष्‍यों तथा उपलब्धियों के कारणों सहित इसके परिणामों का ब्‍यौरा क्‍या है; और
3. सौर ऊर्जा के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्यों में कम निवेश किए जाने के क्‍या कारण हैं तथा सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के उत्‍पादन को कई गुणा बढ़ाने के लिए यदि कोई कदम उठाए जाने का विचार है तो वे क्‍या हैं ?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

 **(श्री पीयूष गोयल)**

1. : वर्ष 2010 में राष्‍ट्रीय सौर मिशन की शुरूआत के बाद सौर ऊर्जा से विद्युत उत्‍पादन हेतु संयंत्रों की संस्‍थापना पर लगभग 30,000 करोड़ रू. का निवेश किया गया है ।
2. : इस निवेश के परिणामस्‍वरूप देश में दिनांक 30/06/2014 तक लगभग 2686 मेगावाट ग्रिड संबद्ध और 125 मेगावाट ऑफ-ग्रिड सौर विद्युत उत्‍पादन क्षमता स्‍थापित की गई है । चूंकि सौर ऊर्जा क्षेत्र एक उदीयमान क्षेत्र है इसलिए लक्ष्‍य एवं उपलब्धियां कम नहीं हैं और नीचे दर्शाई गई हैं :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| मिशन की अवधि  | ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत के लिए लक्ष्‍य (मेगावाट) | उपलब्धियां (मेगावाट) |
| चरण-।(2010-13)  | 1100 | 1686 |
| चरण-।। (2013-17)  | 9000 | **1000****(30.**06.2014 **तक**) |

1. : सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास विश्‍व-स्‍तर पर जारी है और यह मुख्‍यत: उद्योग द्वारा संचालित हो रहा है । मंत्रालय राष्‍ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत भारतीय संस्‍थानों द्वारा उद्योग की साझेदारी से विशिष्‍ट लक्ष्‍य युक्‍त परिणामों के साथ जुड़़े अनुप्रयुक्‍त अनुसंधान और विकास कार्य कलापों को सहायता प्रदान कर रहा है जिसके लिए परियोजना लागत के 50 % तक की वित्‍तीय सहायता दी जा रही है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए पांच उत्‍कृष्‍टता के केंद्रों की भी स्‍थापना की गई है ।

 सरकार देश में सौर विद्युत के उत्‍पादन को कई गुणा बढ़ाने के लिए निम्‍नलिखित प्रमुख कदम उठा रही है :

* वर्ष 2022 तक ग्रिड-संबद्ध सौर ऊर्जा की 20,000 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने के दीर्घकालिक लक्ष्‍य के साथ, जिसे 3 चरणों में प्राप्‍त किया जाना है (प्रथम चरण-वर्ष 2012-13 तक, द्वितीय चरण-वर्ष 2013 से 2017 तक और तृतीय चरण- वर्ष 2017 से 2022 तक), देश में विद्युत उत्‍पादन के साथ-साथ प्रत्‍यक्ष तापीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से राष्‍ट्रीय सौर मिशन का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है ।
* राष्‍ट्रीय शुल्‍क-दर नीति के अतंर्गत सौर विशिष्‍ट आर.पी.ओ. {चरण-। (वर्ष 2013) में 0.25% जिसे वर्ष 2022 तक 3% तक बढ़ाया जाना है}, राज्‍य विशिष्‍ट सौर नीतियां एवं आर.पी.ओ. लक्ष्‍य और अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) संबंधी कार्यतंत्र जैसे उपायों के माध्‍यम से एक समर्थकारी नीति और विनियामक परिवेश तैयार किया जा रहा है । डिस्‍कोम्‍स तथा इकरारबद्ध (ऑबलिगेटेड) कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ।
* सौर विद्युत उत्‍पादन एककों की व्‍यवहार्यता में वृद्धि लाने के लिए त्‍वरित मूल्‍यहृास, रियायती/शून्‍य उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क, अधिमान्‍य शुल्‍क-दर और उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहनों के रूप में राजकोषीय एवं वित्‍तीय प्रोत्‍साहन दिए जा रहे हैं ।

............